[श्री रंगा]

सरकार इनसे 827 करोड़ रुपये तो केवल उत्पादन-शुल्क के रूप में ले लेती है जोकि प्रतिरक्षा तथा प्रशासन पर होने वाले व्यय के बराबर है । इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे हम इस वित्त विधेयक तथा आयव्ययक प्रस्थापनाओं का समर्थन करें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा दल इस सरकार तथा सत्तारूढ़ दल का इस सदन में और देश में संसदात्मक तथा लोकतन्त्रात्मक तरीके से विरोध करता है और यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम इनकी असफलताओं को प्रकाश में लायें और लोगों को बतायें कि यह सरकार वास्तव में समाजवादी नहीं है, यह गांधीवादी नहीं है । यह सरकार लोगों को गरीब बनाना और देश को वित्तीय तथा सामाजिक रूप से नष्ट करना चाहती है ।

कच्छ-सिन्ध सीमा की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION ON KUTCH-SIND BORDER

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं ने कुछदिन पूर्व कच्छ-सिन्ध सीमा विवाद के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण समझौता करने के लिये ब्रिटिश प्रधान मंत्री, श्री हरोल्ड विल्सन द्वारा की गई पहल का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है वह यह है कि गत रात ब्रिटिश उच्च आयुक्त से ब्रिटिश प्रस्तावों का अग्रेतर ब्यौरा प्राप्त हुआ है । यह ब्यौरा कल पाकिस्तान सरकार को भी भेजा गया था । लार्ड माऊंटबेटन ने, जिन्होंने भारत की यात्रा पूर्णरूप से एक भिन्न प्रयोजन के लिये की थी, इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रखे हैं ।

हम इन सुझावों पर मूल सिद्धांतों के आधार पर जो मैंने पहले ही सभा के समक्ष रख दिये थे, विचार किया जा रहा है । इन प्रस्तावों के ब्योरे के बारे में कोई सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देना उचित नहीं होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में राजनयिक माध्यम से विचार-विमर्श अभी जारी है । यह अनिवार्य है कि पाकिस्तान बलप्रयोग की धमकी देना छोड़कर अपने सैनिकों को उन स्थानों से हटा लें जिन पर उनका पहले कब्जा नहीं था । कई दिनों से वहां पर लड़ाई बन्द है । जबकि शांतिपूर्ण समझौता करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, हमारी सशस्त्र सेना स्थिति को बिगाड़ने के लिये कुछ नहीं करेगी जब तक कि दूसरी ओर से उन्हें उत्तेजित नहीं किया जायेगा ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या प्रधान मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने अपने अन्तिम वाक्य में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें और युद्ध विराम में क्या अन्तर है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : युद्धविपाम का अर्थ युद्ध विराम की नियमित घोषणा करना है । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब तक युद्ध पूर्व यथास्थिति को लाने के सिद्धांत को नहीं माना जायेगा तब तक युद्ध-विराम नहीं होगा । मैं ने अपने वक्तव्य के अन्त में यह कहा है कि अभी वहां पर लड़ाई बन्द है, फिर भी कभी कभी गोलाबारी होती रहती है । कोई नहीं जानता कि किस समय लड़ाई छिड़ जाये, परन्तु इस समय वहां पर शान्ति है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : क्या हमने, वास्तव में, इस आशा से कि ब्रिटेन द्वारा किये गये प्रयत्नों के सफल होने की सम्भावन है, उन पर निर्भर करते हुए लड़ाई बन्द कर दी है ? क्या प्रधान मंत्री को यह वक्तव्य नहीं देना चाहिये कि हमने व्यवहारिक

रूप से युद्धविराम को मान लिया है और यदि हां, तो क्या यह प्रधान मंत्री द्वारा देश को दिये गये आश्वासन के विरूद्ध नहीं है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, नहीं। जैसा कि मैं ने बताया कि यह सुझाव दिया गया था कि जहां तक हो सके वहां पर शांति बनाई रखी जाये। जहां तक मुझे पता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान कभी कभी गोली चला देता है, परन्तु उन्होंने बड़े पैमान पर कोई उद्वेजक कार्यवाही नहीं की है। अलबत्ता हमने भी कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही नहीं की है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि जनवरी, 1960 में मंत्री स्तर पर जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंत में जारी की गई विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया था कि दोनों देश कच्छ-सिन्ध सीमा विवाद को निपटाने के लिये अग्रेतर तथ्यांक एकत्र करने के कुछ समय बाद बातचीत करने पर सहमत हो गये हैं ; और यदि हां, तो क्या तथाकथित झगड़े के बारे में बाद में बातचीत हुई थी ? क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि उस समय कोई झगड़ा था ? क्या प्रधान मंत्री जी को इस विज्ञप्ति तथा इस तथाकिथत झगड़े का पता था जब उन्होंने इस वर्ष मार्च में अथवा कुछ समय बाद कच्छ के बारे में अपना वक्तव्य दिया था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, हां। जो कुछ आपने कहा है वह पूर्ण रूप से सही है। यह सब कुछ वदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा 8 अप्रैल को दिये गये वक्तव्य में कहा गया था। परन्तु जो कुछ मैंने कहा है वह यह है कि चाहे कोई भी मतभेद हो इसका सम्बन्ध केवल सीमा-रेखा से है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारे और पाकिस्तान के बीच किसी किस्म का कोई राज्य क्षेत्रीय झगड़ा है। अलबत्ता सीमा-रेखा के बारे में बातचीत की जा सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या यह सच है कि लन्दन के एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान तथा भारत में युद्ध बन्द करने पर सहमत हो गये हैं और ब्रिटिश प्रधान मंत्री आज रात को हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य देंगे ? प्रधान मंत्री का इस से इस कथन का क्या आशय है कि "जब तक कि उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती"। पाकिस्तान ने हमारे राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है क्या यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं है ? क्या हम उन्हें वहां से खदेड़ने की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक उत्तेजनात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध है यह तो केवल समय का प्रश्न है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम उन्हें वहां से निकालने का हर प्रयत्न करेंगे। जहां तक युद्ध-विराम के बारे में समझौते की बात है, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। मैं यह भी बता दूं कि वास्तव में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने एक सप्ताह के लिये युद्ध बन्द करने के बारे में एक औपचारिक प्रस्ताव रखा था, परन्तु हमने उसे रद्द कर दिया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : क्या यह सच है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री यह चाहते थे कि जब तक कोई नई उत्तेजनात्मक अथवा आक्रमका कार्यवाही नहीं की जाती तब तक शांति बनाई रखी जानी चाहिये ; और यदि हां, तो क्या हमने ब्रिटिश प्रधान मंत्री के इस सुझाव को मान लिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह सच है कि उन्होंने यह सुझाव दिया था । परन्तु हम महसूस करते हैं कि जब तक यह बातचीत जारी रहेगी और जब तक पाकिस्तान वर्तमान स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा तब तक हम भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे स्थिति में कोई बिगाड़ पैदा हो ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Mr. Speaker, in a Pakistani map circulated to all Members of Parliament to-day morning, Ding, Kanjarkot, Sardar Post, Wigkot, Biar Bet, Karimshahi, Gulu Talab and Chand have been shown as parts of Pakistan. Have Government brought this to the notice of the countries of the world that these maps are incorrect and we are not prepared to negotiate with Pakistan untill and unless these places are vacated by them?

Shri Lal Bahadur Shastri: In so far as getting these places vacated, is concerned, our policy is very clear that so far as these territories are not vacated by them, there will be no cease-fire. As regards sending of maps to foreign countries, we have already sent maps along with a pamphlet.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): To-day the position is this that Pakistan is occupying our territory and the peace makers say that there should be a cease-fire. We have practically agreed to their proposal and are not taking any action. For how long this situation will remain and after how many days we take action to drive them out?

Shri Lal Bahadur Shastri: This situation will end soon. We have already told the British Prime Minister that we cannot afford to wait for a number of days. There is no doubt about it that we will settle this matter very soon.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The various statements made by the Prime Minister at different places during one week are contradictory. In a statement made by him in Lok Sabha he said that the question of any talk did not arise so long as the *status-quo ante* was not brought about. In Rajya Sabha he said that we could not wait for a very long time in this matter. But at one place he said that we would get Kanjarkot vacated in 5-6 months' time. I want to know after all what is in his mind? The Britishers want to prolong the matter so that the area is submerged under sea-water and no change is brought about in the present position. The country should at least be told as to when this area would be got vacated and for how long we would have to go on pocketing this insult?

Shri Lal Bahadur Shastri: I do not understand as to how far it is proper for the hon. Member to say all this. We should exercise some self restraint at this juncture. So far as time is concerned, as I said, we want to settle this matter without any delay and it was due to this fact that we have to say that we are unable to tolerate any further delay in this matter. As regards cease-fire, there will be no cease-fire unless the principle of restoration of the *status quo ante* is also agreed to. At the same time they will have to be accepted that while cease-fire would be brought about immediately, but the actual vacation of the area would take some time.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा कि जब तक हमें उत्तेजित नहीं किया जायगा तब तक हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे स्थिति में कोई बिगाड़ पैदा हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की निरन्तर उपस्थिति उत्तेजनात्मक कार्यवाही है अथवा नहीं और क्या हमें यह जो अपमानजनक तथा निरर्थक साहित्य और नक्शे जिनमें हमारे क्षेत्र को पाकिस्तान में दिखाया गया है, मिल रहे हैं, क्या यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही है अथवा नहीं ; और यदि यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसी कार्यवाही है जो भारत सरकार को उत्तेजित करेगी जिससे कि वे प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने पर मजबूर हो जाये, जबकि अभी बातचीत भी चल रही हो ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बातचीत जारी रहेगी तब तक हमारी सेनायें स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगी। अन्यथा हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं और हम क्या करना चाहते हैं। साहित्य अथवा नकशों के के बारे में मैं छानबीन करूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Shri Wilson and his friend, Shri Johnson are either ignored about India or they want to make India a scape goat. This is clear from their policy in regard to North Vietnam; while they are ready to start firing there, but they did not attack Chinese forces when they attacked India. I want to urge upon the Government to declare that there would be no cease-fire unless the Kanjarkot and other areas are taken back from Pakistanis.

Shri Lal Bahadur Shastri: I have already made it clear that we are not ready to part with an inch of our territory and we would not hesitate to do whatever is necessary for that.

वित्त विधेयक, 1965—जारी

FINANCE BILL, 1965—*contd.*

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : वित्त विधेयक में बहुत सी असंतोषजनक बातें हैं और मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। परन्तु मैं उन सब बातों का उल्लेख न करके केवल एक ह विशेष बात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह वित्त मंत्री के ध्यान में लाया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका से जो हम वित्तीय-व्यवहार करते रहे हैं इससे न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था को परन्तु हमारे देश की स्वतन्त्रता तथा विकास को धक्का पहुंचा है।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

वित्त मंत्री ने बताया कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो सौदे हुए हैं उनसे हमारी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति सम्बन्धी कोई खतरा नहीं है। इसको भी यदि मैं मान लूं क्योंकि मुद्रास्फीति के और कई कारण हैं। 20 नवम्बर, 1964 तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत लगभग 1421.9 करोड़ रुपये के सौदे हुए हैं। 80 करोड़ रुपये गैर-सरकारी उपक्रम के लिए उपलब्ध किये गये हैं और 105.3 करोड़ रुपये अमरीकी सरकार के भारत